भारत में ज्यादा आबादी और कम कृषि

कृषि कुंभ (फरवरी, 2023),
खण्ड 02 भाग 09, पृष्ठ संख्या 35–36

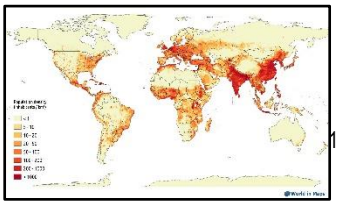

भारत में ज्यादा आबादी और कम कृषि

अमर सिंह[1] एवं [2]पायल चौधरी

[1]परास्नातक शोध छात्र (कीट विज्ञान), [2]परास्नातक शोध छात्र (प्रसार शिक्षा)
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर राजस्थान, भारत।

Email Id: amarchahar15@gmail.com

अर्थव्यवस्था के विकास और व्यवस्था पर जनसंख्या की निर्भरता के लिए कृषि हमेशा चर्चा का एक बड़ा विषय रहा है। भारत एक विकासशील देश है और भारत में पचहत्तर प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश होने के नाते भारत में ग्रामीणों और किसानों की जनसंख्या बहुत ज्यादा हैं जो देश के विकास को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। आबादी का भारी बहुमत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और दैनिक जरूरतों की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। ऐसी स्थिति में जहां कृषि लोगों के जीवन का समर्थन करती है, वहीं किसानों और अन्य क्षेत्र के लोगों की पूरी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर रही है। हम ग्रामीण क्षेत्रों से आच्छादित हैं और पिछले वर्षों से, ग्रामीण क्षेत्र राष्ट्र की व्यवस्था को उन्नत करने के लिए आर्थिक रूप से बढ़ रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत ने एक अरब जनसंख्या रैंक को पार कर लिया है और चीन की जनसंख्या को पार करने का अनुमान है। अब मनुष्य के मन में सबसे बड़ी खोज यह उठती है कि भारत में कृषि कैसे भारतीय लोगों के जीवन का समर्थन करेगी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि में। हमारा देश जनसंख्या वर्द्धी की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। भोजन की कमी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट, कुपोषण और कई गंभीर परिस्थितियों में भारत विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है। जबकि बढ़ती हुई जनसंख्या को कई तरह से बड़ी समस्याएं नजर आती हैं। यदि इस स्थिति में लोगों की कृषि आजीविका के मुख्य स्रोत को रोका नहीं गया तो यह देश के लिए एक बड़ी बाधा हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कम पेयजल, बेरोजगारी, कम कृषि व्यवस्था, फसलों का कम उत्पादन आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए लोगों ने खुद को शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का समाधान ढूंढा। वहा लोगों को रोजगार, अच्छा भोजन और पानी के अवसर मिल रहे हैं। उपकरण और मशीनों के मानक के साथ फसलों के अच्छे उत्पादन की आशा आदि। तो, ये बड़ी चुनौतीपूर्ण समस्याएं और खतरे थे जिनका सामना देश के लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। आइए चर्चा करें कि ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है।

कम कृषि प्रणाली और अधिक जनसंख्या के साथ दूर करने के लिए सरकार की कार्रवाई:

कृषि व्यवस्था और जनसंख्या के बढ़ते अनुपात की समस्या को दूर करने के लिए सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एनजीओ संगठन संस्थाओं को जागरूकता कार्यक्रम बनाकर और प्रमुख स्थिति से निपटने के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करके एक बहुत ही प्रभावी योजनाबद्ध कदम उठाया गया है। जनसंख्या के संदर्भ में लोगों को शिक्षित करने और भारत में कृषि के बेहतर संसाधन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा बेहतर अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार ने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं। पीएम किसान

योजना, पीएम सम्मान निधि योजना इन योजनाओं के माध्यम से आय और आय के अन्य स्रोतों में वृद्धि करके किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई प्राथमिक योजनाएँ हैं। सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन और संस्थान अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बड़े पैमाने पर भाग ले रहे हैं और लोगों को कृषि प्रणाली के माध्यम से आजीविका के महत्व के बारे में पुरस्कृत कर रहे हैं। कृषि आजीविका को लेकर लोग अपने जीवन को स्वयं के माध्यम से बनाए रख सकते हैं और शांति और आराम से रह सकते हैं।

जनसंख्या और कृषि की निर्भरता:

भूमि श्रम और पूंजी को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादकता में सुधार किया जाना चाहिए। भारतीय जनसंख्या कृषि प्रणाली पर आधी निर्भर है और कृषि फसलों के उत्पादन में समृद्ध है। इसका अर्थ है कि सरकार को मानक उत्पादों और कच्चे माल के लिए उपयोग की जाने वाली फसलों की बड़ी किस्मों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बेहतर फसल उगाने के लिए कृषि किसानों को बेहतर कृषि उपकरण आदान प्रदान किया जाना चाहिए और बड़े पैमाने पर लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। लाभकारी प्रथाओं के आश्वासन में शामिल कारक जैसे भूमि उर्वरक, बीज, फसल बीमा कृषि से संबंधित गतिविधियों के साथ एक दूसरे के अवलोकन पर निर्भर करते हैं। इन गतिविधियों पर दोनों दृष्टिकोण से ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि पर आजीविका के लिए लोगों के हिस्से पर निर्भर है चाहे इसमें भूस्वामी, किरायेदार किसान और कृषि किसान शामिल हों जो इन भूमि खेतों पर कार्यरत हैं। सरकार को इन योजनाओं के लिए तत्पर रहना चाहिए और इनकी सुरक्षा के लिए इन प्रतिभूतियों में योगदान करना चाहिए और उचित परिणाम देना चाहिए। देश की जनसंख्या और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। बेहतर फसल उत्पादन या परिणाम के लिए विभिन्न योजनाओं और रणनीतियों को विकसित किया जाना चाहिए। खाद्य और कृषि संगठन के प्रमुख प्रतिभागी लोगों की खाद्य सुरक्षा और पोषण को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर संबोधित कर रहे हैं। लोगों की प्राथमिक आहार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत से कुपोषण की समस्या को खत्म करने के संदर्भ में डेयरी खाद्य उत्पादों के उत्पादन और निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। किसानों के लाभ के लिए सरकार द्वारा अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण योजनाओं का उद्घाटन किया जाता है।

निष्कर्ष

कृषि और भारत की जनसंख्या इसके विपरीत हैं क्योंकि देश की जनसंख्या भोजन, पानी और कृषि आजीविका प्रणाली पर निर्भर करती है। कृषि प्रणाली लोगों की जरूरतों के लिए प्रमुख खरीद है और इस प्रकार इसे व्यवस्थित और स्वतंत्र रूप से केंद्रित किया जाना चाहिए। कृषि प्रणाली के बेहतर विकास के लिए विभिन्न उपकरणों और मशीनरी फसल उत्पादन गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके लिए लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन और अन्य प्राथमिक जरूरतों को अच्छी गुणवत्ता में उपलब्ध कराने में सरकार को गहरी दिलचस्पी लेनी चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि में बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। देश की जनसंख्या विशाल है इसलिए यह लोगों का कर्तव्य है कि वे भविष्य की चिंता के लिए हमारी कृषि आजीविका की रक्षा करें और इसे सुरक्षित रखें। यह संभव हो सकता है अगर सरकार की योजनाओं और नीतियों द्वारा किए गए सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए। कृषि प्रणाली के विकास को बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा कई योजनाएँ और रणनीतियाँ अपनाई जानी चाहिए जो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी मदद करती हैं।